सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उद्घोषणा है 'वंदे मातरम्'

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 - अंक : 08 - नवंबर 2025

कोऑपरेटिव बैंकिंग में डिजिटल क्रांति

हर शहर में खुलेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक

डिजिटल क्रांति से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन

सहकारिता, कृषि और मछली पालन से दूर हो रही गरीबी, बढ़ रहा रोजगार 22

आलू के उन्नत बीज तैयार करने की उल्लेखनीय पहल 26

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
नवंबर 2025, अंक 08, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा
समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें :
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते :

MINISTRY OF COOPERATION

NCUI हाट | CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

आवरण कथा

06

कोऑपरेटिव बैंकिंग में डिजिटल क्रांति

पैक्स सहित सभी कोऑपरेटिव सोसायटी का कंप्युटराइजेशन किए जाने से कोऑपरेटिव सेक्टर को डिजिटलीकरण करना आसान हो गया है। इसी कड़ी में आगे कदम बढ़ाते हुए पेमेंट और लोन सिस्टम को डिजिटल बनाने की पहल की गई है।

12

स्वाधीनता सेनानियों का गीत होने के साथ ही शाश्वत प्रेरणा भी है

वंदे मातरम् केवल एक शब्द नहीं है - यह एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है और एक पवित्र संकल्प है। यह मां भारती के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है।

राष्ट्र जागरण का प्रथम मंत्र है 'वंदे मातरम्' **14**

रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें **16**

दुग्ध उत्पादों के निर्यात से देश की सहकारी समितियां हो रहीं समृद्ध **18**

भारत अब दुनिया के लिए विश्वसनीय एवं जिम्मेदार साझेदार : प्रधानमंत्री **20**

सहकारिता, कृषि और मछली पालन से दूर हो रही गरीबी, बढ़ रहा रोजगार **22**

सरकार ने किसानों के हित में किए व्यापक सुधार **24**

29

सौर ऊर्जा का उत्पादन कर किसानों ने दिखाई नई राह

डिजिटल क्रांति से मजबूत हो रही सहकारिता

भारत में सहकारिता क्षेत्र में नवाचारों, सरकारी पहलों और सहकारी सुधारों का बुनियादी प्रभाव दिखने लगा है। सहकारिता मंत्रालय के 100 से अधिक बहुआयामी पहलों के परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्र का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण और उन्हें बहुउद्देशीय बनाने के बाद अभी हाल ही में नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों को डिजिटल नवाचारों, शासन सुधारों और वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाने पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और वंचितों को सशक्त बनाने की पहल की गई। राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समिति महासंघ (नैफकब) द्वारा आयोजित शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के इस वैश्विक सम्मेलन में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत से सकारात्मक पहल किए गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया और कहा प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक के वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप देने की अपील की।

दरअसल, भारत सरकार और सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के साथ-साथ समाज के वंचित वर्गों का उत्थान और ग्रामीण सशक्तीकरण का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। देश के सभी गांवों व सुदूर ग्रामीण अंचलों तक सहकारी समितियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो लाख नई समितियों के गठन की दिशा में करीब 30 हजार प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स), डेयरी एवं मत्स्य समितियों की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह, शहरी सहकारी बैंकों के विस्तार की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने दो लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में पांच वर्षों के भीतर एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही, छोटी शहरी सहकारी समितियों को भी डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए उन्हें 'सहकार डिजी-पे' और 'सहकार डिजिलोन ऐप' से जोड़ने की पहल की है। निश्चय ही इन पहलों से भारत के शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूती मिलेगी, जिससे जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और उन्हें देश की वित्तीय प्रणाली में एक प्रमुख भागीदार के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी।

सरकार के इन प्रयासों का लक्ष्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को कार्पोरेट बैंकों के समान सुदृढ़ और कार्यक्षम बनाकर उन्हें देशवासियों का भरोसेमंद बैंक बनाना है, जिससे सहकारी बैंकों का कायाकल्प हो सके। इस अभिनव पहल से छोटे शहरी सहकारी बैंक भी बहुत सस्ती लागत पर साइबर सुरक्षा, लचीलापन, आपदा रिकवरी और बैकअप सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे और वे देश में मजबूत, आधुनिक और सक्षम बैंक के रूप में पहचान पा सकेंगे।

सहकारी क्षेत्र के विविध पहलों के प्रभावस्वरूप भारतीय सहकारी क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तनों से सहकारी सदस्यों और समुदाय के बीच विश्वास का निर्माण हो रहा है। यह सहकारी समितियों की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों ने अब स्वयं को आधुनिक आर्थिक प्रथाओं के साथ जोड़ लिया है और अब वे सतत विकास लक्ष्यों में प्रभावी रूप से योगदान दे रही हैं। इन पहलों से सक्षम और सामर्थ्यवान हुईं सहकारी समितियां निश्चय ही अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में जीवंत डिजिटल उद्यमों के रूप में चमकेंगी।■

जय सहकार

'विकसित भारत' का रास्ता हमारे अन्नदाता भाई-बहनों की समृद्धि से जुड़ा है, इसलिए उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराना हमारी बड़ी प्राथमिकता रही है। अपने किसान, पशुपालक और मछुआरा भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। बीते 11 वर्षों में हमने बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म्स किए हैं। लखपति दीदी से लेकर ड्रोन दीदी तक आज हमारी माताएं-बहनें और बेटियां गांवों की समृद्धि बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। खेती को आधुनिक बनाने में भी वे बहुत मददगार हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

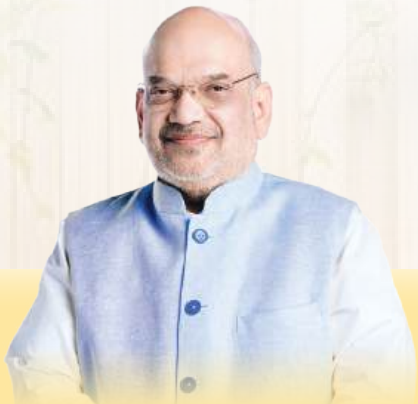

मोदी सरकार सहकारिता को नई नीतियों, तकनीकों और नवाचारों से सशक्त बनाकर 'सहकार से समृद्धि' के मूलमंत्र को साकार कर रही है। नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'कोप कुंभ 2025' से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डिजिटलीकरण और विस्तार का रोडमैप बना है। यहां हर शहर में कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना का लक्ष्य भी निर्धारित हुआ है, जिससे सहकारी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को और अधिक रफ्तार मिलेगी। साथ ही, यहां लॉन्च हुए 'सहकार डिजी-पे' और 'सहकार डिजी-लोन' ऐप सहकारिता को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और जन उपयोगी बनाएंगे।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पहले जहां महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, वहीं आज वे आत्मनिर्भर बन न सिर्फ अपने परिवार को सशक्त बना रही हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही हैं। लखपति दीदी योजना झारखंड, ओडिशा, गुजरात समेत देशभर की महिलाओं की तकदीर बदल रही है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

फिट इंडिया, हिट इंडिया! मोदी सरकार की 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' के विजन के साथ पूरे देश में लागू की गई स्पोर्ट्स पॉलिसी युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति नई प्रेरणा दे रही है। इसका यह अच्छा उदाहरण है कि पुणे में तेजी से फैल रहा स्पोर्ट्स कल्चर अब लोकल लेवल पर भी मजबूत हो रहा है। ऐसी एक्टिविटीज समाज में एक हेल्दी और कॉम्पिटिटिव सोच पैदा करके 'फिट इंडिया, हिट इंडिया' के कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रही हैं।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के समग्र विकास हेतु नीति-आधारित नवाचार, उन्नत तकनीक के प्रसार और बाजार-सुलभता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है। पीएम-किसान योजना के माध्यम से करोड़ों कृषक परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति प्राप्त हो रही है।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

मन की बात का 127वां एपिसोड

पर्यावरण संरक्षण के लिए देशवासियों का आह्वान

सहकार जागरण टीम

अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के 127वें एपिसोड में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न उदाहरणों को पेश करते हुए देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण व साफ-सफाई के प्रति प्रेरित किया और इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

छतीसगढ़ के अम्बिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए अम्बिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक अनोखी पहल गारबेज कैफे का जिक्र करते हुए पीएम श्री मोदी ने लोगों को स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि इस कैफे में प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक लेकर जाए उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो कैफे की ओर से उसे नाश्ता कराया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा की ओर से जल श्रोतों की साफ-सफाई और उन्हें नया जीवन देने के लिए चलाए जा रहे अभियान का उल्लेख किया। झीलों का शहर कहे जाने वाले बेंगलुरु में कपिल शर्मा ने झीलों को पुनर्जीवित करने की मुहिम छेड़ी है। अब तक कपिल और उनकी टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुंओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव होकर ही रहता है।

बदलाव के एक और प्रयास का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में जंगल मिट्टी को बांधे रहते हैं, कुछ वैसी ही अहमियत समुद्र के किनारे मैंग्रोव की होती है। मैंग्रोव के पेड़ समुद्र के खारे पानी और दलदली जमीन में उगते हैं और समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा होते हैं। सुनामी या चक्रवात जैसी आपदा आने पर ये मैंग्रोव बहुत मददगार साबित होते हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार के वन विभाग ने मैंग्रोव के महत्व को ध्यान में रखते हुए खास मुहिम चलाई है। पांच साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धोलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था। अब धोलेरा तट पर साढ़े तीन हजार हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। वहां डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यहां प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। धोलेरा के अलावा गुजरात के कच्छ में भी इन दिनों मैंग्रोव लगाने का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। वहां कोरी क्रीक में, 'मैंग्रोव लर्निंग सेंटर' भी बनाया गया है। पेड़-पौधों की अहमियत बताते हुए श्री मोदी ने देशवासियों से 'एक पेड़ मां के नाम' के अभियान से जुड़ने और उसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

छठ महापर्व को संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब बताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हों, यदि मौका मिले, तो, छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। ■

- **छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में पर्यावरण संरक्षण में गारबेज कैफे दे रहा महत्वपूर्ण योगदान**
- **बेंगलुरु में कुंओं व झीलों को मिल रहा पुनर्जीवन, गुजरात में लगाए जा रहे मैंग्रोव पारिस्थितिकी को कर रहे मजबूत**

कोऑपरेटिव बैंकिंग में

➲ कॉप कुम्भ-25 में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकार डिजी पे व डिजी लोन ऐप किया लांच
➲ डिजिटल होती सहकारिता से नये युग की शुरुआत, डिजिटल प्लेटफॉर्म से सहकारी संस्थाएं होंगी पारदर्शी

सहकार जागरण टीम

पैक्स सहित सभी कोऑपरेटिव सोसायटी का कंप्युटराइजेशन किए जाने से कोऑपरेटिव सेक्टर का डिजिटलीकरण करना आसान हो गया है। इसी कड़ी में आगे कदम बढ़ाते हुए पेमेंट और लोन सिस्टम को डिजिटल बनाने की पहल की गई है। इसके लिए 'सहकार डिजी पे' ऐप और 'सहकार डिजी लोन' ऐप को लॉन्च किया गया है। डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन सिस्टम आज की जरूरत बन चुका है। कोऑपरेटिव सेक्टर डिजिटल दुनिया में पीछे न रह जाए, इसे देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को-ऑप कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए इसे लॉन्च किया।

इस सम्मेलन का आयोजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अंब्रेला संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (नैफकब) ने किया। इस सम्मेलन का थीम 'डिजिटलाइजिंग ड्रिम्स- सशक्त समुदाय' रखा गया था। को-ऑप कुंभ 2025 के दौरान पॉलिसी, तकनीक और इनोवेशन के विषय पर इस क्षेत्र से जुड़ी कई संभावनाओं का दोहन करने लिए विचार किया गया। साथ ही, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के विस्तार का रोडमैप तैयार करने के लिए 'दिल्ली घोषणा 2025' को प्रस्तुत

डिजिटल क्रांति

दो लाख की आबादी वाले हर शहर में पांच वर्षों में खुलेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, होगा कैशलेस लेनदेन

> मोदी सरकार सहकारिता को नई नीतियों, तकनीकों और नवाचारों से सशक्त बनाकर 'सहकार से समृद्धि' के मूलमंत्र को साकार कर रही है। नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'कोऑपरेटिव कुंभ 2025' से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डिजिटलीकरण और विस्तार का रोडमैप निकलने वाला है हर शहर में कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना का लक्ष्य भी यहां रखा गया है, जिससे सहकारी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को और अधिक रफ्तार मिलेगी। साथ ही, यहां लॉन्च हुए 'सहकार डिजी-पे' और 'सहकार डिजी-लोन' ऐप सहकारिता को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और जन उपयोगी बनाएंगे।
>
> - श्री अमित शाह
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

किया गया।

'सहकार डिजी पे' एक ऐसा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो सहकारी समितियों को पारदर्शी और कैशलेस लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई द्वारा संचालित होगा, जिससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और विश्वास को नई मजबूती मिलेगी। जिनका बैंक खाता कोऑपरेटिव बैंकों में है उनके लिए भी अब डिजिटल पेमेंट आसान हो जाएगा। अभी कोऑपरेटिव बैंकों के ज्यादातर खाताधारक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि बहुत कम ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो डिजिटल पेमेंट की सेवा दे रहे हैं। इससे जल्दी ही 800 से अधिक टियर-1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जुड़ जाएंगे। देश के 1,480 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में से लगभग 80 प्रतिशत टियर-1 और टियर-2 श्रेणियों में आते हैं। इस ऐप से सिर्फ शहरी ही नहीं, दूरदराज के छोटे कोऑपरेटिव बैंकों और उनके ग्राहकों को भी सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

जबकि 'सहकार डिजी लोन' ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देशभर के सहकारी सदस्यों को कागज रहित, त्वरित और पारदर्शी ऋण एवं क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगा। सहकारी बैंकों एवं क्रेडिट सोसायटियों से लोन लेना अब सदस्यों के लिए आसान हो जाएगा। अभी उन्हें इनसे लोन लेने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें समय भी ज्यादा लगता है। सहकार डिजी लोन ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा और उन्हें इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। इन दोनों ऐप का विकास नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) ने किया है और यही इसका संचालन भी करेगी। कोऑपरेटिव सेक्टर में डिजिटल क्रांति से सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर सहकारी आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा।

अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को वंचित वर्गों के विकास में निभानी चाहिए सशक्त भूमिका

इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसायटी के सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। पिछले 3-4 साल में देश

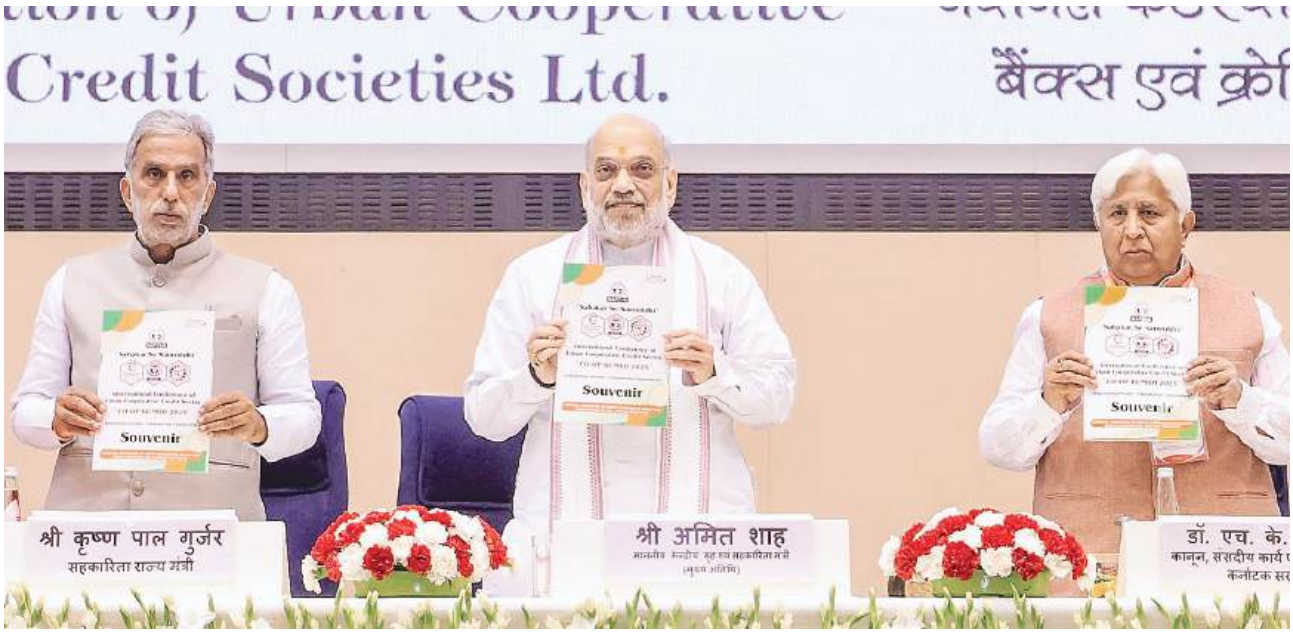

का अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी क्षेत्र नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अगले पांच वर्षों के भीतर दो लाख से अधिक आबादी वाले हर कस्बे में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सरकार ने कोऑपरेटिव से जुड़े हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। इसके साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बनाने, इसकी समस्याओं का समाधान करने और कोऑपरेटिव की पहुंच बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के लिए चार लक्ष्य तय किए हैं। जेनरेशन सहकार का विकास, यानी युवा पीढ़ी को सहकारिता के साथ जोड़ना। इसके लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो सहकारिता क्षेत्र की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगी।

इसी तरह, हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर पाने वाली सहकारी समितियों को भी तैयार करने और अगले 5 वर्ष में 2 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मल्टी-सेक्टर अप्रोच के साथ देश के युवा उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर तबके के लोगों के सशक्तीकरण के लिए काम करना होगा। कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ-साथ कमजोर तबके के लोगों को भी मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों ने पिछले दो साल में एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियों) को 2.8 प्रतिशत से घटाकर 0.06 प्रतिशत करने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही अब संचालन के स्तर में सुधार करना होगा और वित्तीय अनुशासन में आए सुधार को आगे बढ़ाना होगा। हर शहर में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाना तभी संभव है जब कोऑपरेटिव सोसायटी को बैंक में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा।

कॉर्पोरेट बैंकिंग की सुविधाओं से मुक्त हो रहे कोऑपरेटिव बैंक

नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) के चेयरमैन ज्योतिंद्र मेहता ने अपने संबोधन

में देश के कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र के परिवर्तन, लचीलेपन और नए आत्मविश्वास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'अब वह दिन बीत चुके हैं जब सहकारी समितियों को दोयम दर्जे का माना जाता था। अब हम कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ गर्व से खड़े हैं।'

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के नेतृत्व में भारत की बैंकिंग प्रणाली को सबसे लचीली प्रणालियों में से एक माना गया है, मेहता ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, '2021 में हमारा ग्रॉस एनपीए लगभग 21 प्रतिशत था जो आज 7 प्रतिशत पर आ गया है। जबकि शुद्ध एनपीए केवल 1.2 प्रतिशत है। यह देश के प्रत्येक कोऑपरेटिव बैंक के लिए गर्व का क्षण है।'

अमित शाह के 'एक शहर, एक शहरी सहकारी बैंक' के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए ज्योतिंद्र मेहता ने कहा कि यह

पहल अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के संतुलित भौगोलिक विकास को सुनिश्चित करेगी और क्षेत्रीय केंद्रीकरण को रोकेगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भारत का अंब्रेला संगठन जल्द ही दुनिया भर की समान संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। एनयूसीएफडीसी कोऑपरेटिव बैंकिंग की डिजिटल रीढ़ होगी जो मजबूत, सुरक्षित और जन-केंद्रित होगी।'

डिजिटल क्रांति से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन

अंब्रेला संगठन को सहकारिता की अगली सदी की ओर पहला कदम बताते हुए मेहता ने कहा कि यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक संरचनात्मक, वित्तीय और डिजिटल आधार प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि को-ऑप कुंभ 2025 सहकारी ऋण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। टेक्नोलॉजी और एकजुटता भारतीय सहकारी समितियों के भविष्य को परिभाषित करेंगे और इस एकता के माध्यम से हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी भारत का निर्माण करेंगे।

वित्तीय समावेशन को तकनीकी नवाचार से जोड़ना समय की मांग

कर्नाटक के विधि, पर्यटन एवं संसदीय कार्य मंत्री और नैफकॉब के मानद अध्यक्ष डॉ. एच. के. पाटिल ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ और टिकाऊ बनाने के लिए नए नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक से संकटग्रस्त बैंकों को बंद करने की मानसिकता छोड़ उनका पुनरुद्धार करने का आग्रह किया। समन्वित संस्थागत प्रयासों के माध्यम से यस बैंक के पुनरुद्धार का उदाहरण देते हुए उन्होंने संकटग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इसी तरह के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का सुझाव दिया। सम्मेलन के विषय, 'डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स, सशक्त समुदायों' पर प्रकाश डालते हुए डॉ. पाटिल ने कहा कि अगले दशक की मांग है कि सहकारी समितियां वित्तीय समावेशन को तकनीकी नवाचार के साथ जोड़ें। उन्होंने सुशासन, डिजिटल को अपनाने, एमएसएमई ऋण विस्तार और जर्मनी, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों के सहकारी मॉडलों से वैश्विक सीख पर केंद्रित भविष्य के दृष्टिकोण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की।

कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहलों की सराहना करते हुए उन्होंने कि सहकारिता मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारी आंदोलन 'विश्वास, पारदर्शिता और परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है जहां सहकारी मॉडल न केवल एक आर्थिक प्रणाली के रूप में, बल्कि समावेशी विकास के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा है।'

सम्मेलन के समापन सत्र में नैफकब के उपाध्यक्ष मिलिंद काले ने 'दिल्ली घोषणा-पत्र 2025' प्रस्तुत किया जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों से अनुपालन को मजबूत करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और डिजिटल गवर्नेंस को अपनाने का आह्वान किया गया। घोषणा-पत्र में साइबर सुरक्षा, डेटा रिपॉजिटरी, ग्रीन फाइनेंस और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला गया और इस बात पर जोर दिया गया कि सहकारी समितियां केवल ऋण प्रदाता ही नहीं हैं, बल्कि सशक्तीकरण और आपसी विश्वास का माध्यम भी हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सहकारिता को नई नीतियों, तकनीकों और नवाचारों से सशक्त बनाकर 'सहकार से समृद्धि' के मूलमंत्र को साकार कर रही है। पिछले तीन-चार वर्षों में देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्षेत्र और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी क्षेत्र नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण से लेकर शहरी अर्थव्यवस्था तक वित्तीय समावेशन, लघु उद्यम प्रोत्साहन और सामुदायिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से समावेशी विकास, सामुदायिक सशक्तीकरण एवं सतत सहकारी भविष्य साकार हो सकता है। ■

एनसीडीसी से सहकारिता को मिली गति

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का वित्तीय दायरा बढ़ने से सहकारिता के विकास को गति मिली है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनसीडीसी सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने में सबसे आगे है। सहकारी संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए इसने अपना दायरा बढ़ा दिया है। कृषि विपणन एवं निवेश, प्रसंस्करण और भंडारण क्षेत्रों को सहायता देने और देश में युवाओं की आय को बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाने से एनसीडासी का दायरा व्यापक हो गया है। देश में इस समय आठ लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनके 29 करोड़ किसान सदस्य हैं।

वर्ष 1963 में अपनी स्थापना के बाद से एनसीडीसी कृषि और बागवानी सहकारी समितियों सहित अन्य सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। एनसीडीसी की क्षमता को पहचानते हुए इसे सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए सहयोग के साथ ही एफपीओ के रूप में नई सहकारी समितियों का पंजीकरण और उन्हें समर्थन प्रदान करती है। निर्यात, जैविक और बीज उत्पादन पर गठित तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर भी एनसीडीसी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

अर्बन सहकारी बैंक बन रहे हैं छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और युवाओं के उत्थान के माध्यम

- नवाचार के नए दौर में प्रवेश कर रही है भारत के सहकारी बैंकों की विकासयात्रा
- विश्वास, तकनीक और वित्तीय पारदर्शिता के अद्भुत अध्याय की हुई शुरुआत
- सहकारिता से सशक्त आम नागरिक के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रहे यूसीबी
- सहकारिता को और अधिक सुलभ, पारदर्शी व जन उपयोगी बनाएंगे
- सहकारी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को मिलेगी और अधिक रफ्तार

सहकार जागरण टीम

कॉप-2025 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस महा आयोजन के माध्यम से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) के विस्तार का काम बहुत जल्दी पूरा होगा। 1,500 से अधिक सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि और 50,000 से अधिक क्रेडिट सोसाइटी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से कोऑपरेटिव से जुड़े हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बैंकों में परिवर्तित करने पर जोर दिया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र के आधुनिकीकरण, इसकी कठिनाइयों के निवारण और कोऑपरेटिव की पहुंच बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

भारत की सहकारिता एक नए युग में प्रवेश कर रही है जहां परंपरा, प्रौद्योगिकी, स्थानीय सोच और वैश्विक दृष्टिकोण मिलकर विकास की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। देश की सभी राज्य सरकारों ने पैक्स के मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है। कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रशिक्षित और दक्ष प्रतिभाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए गठित 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' सहकारी क्षेत्र के लिए युवा प्रोफेशनल्स तैयार कर सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये पहल सहकारिता को देश के ग्रामीण अंचलों में भी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नई

कोऑपरेटिव सोसायटी को बैंक में परिवर्तित करने पर जोर

सहकारी बैंकों का एनपीए घटकर 0.06 प्रतिशत पर आ गया है। सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन बढ़ा है, जिससे उनकी वित्तीय स्थितियों में सुधार हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सहकारी बैंकों में सुधार को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले सहकारी बैंकों का गैर निष्पादित (एनपीए) 2.8 प्रतिशत तक था, जिस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन में हुए सुधारों को भी आगे बढ़ाना होगा। हर शहर में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाना तभी संभव है जब हम कोऑपरेटिव सोसायटी को बैंक में परिवर्तित करने का प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े हमारी प्रगति के मानक नहीं हो सकते। इसके साथ ही यह प्रयास भी होना चाहिए कि हर व्यक्ति को कुछ काम मिले और उसका जीवन स्तर बढ़े, जो कि सहकारिता के बिना संभव नहीं। श्री शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट और महत्व को भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें पूरी तरह से समझती हैं। उन्होंने सभी से एक नए विश्वास और मेहनत के साथ पारदर्शी और परिणामोन्मुखी तरीके से काम करने की अपील की।

उपलब्धियां अर्जित करेंगे। ये ऐतिहासिक पहल सहकारिता को ग्रामीण सशक्तीकरण और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में विश्व में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।

यूसीबी के माध्यम से कमजोर व्यक्तियों का सशक्तीकरण

इस मौके पर नैफकब द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन करके श्री शाह ने कहा कि हमने सहकारिता मंत्रालय के लिए चार लक्ष्य तय किए हैं, जिनमें हमारी युवा पीढ़ी को सहकारिता के साथ जोड़ना सर्वप्रमुख है और इसके लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो सहकारिता क्षेत्र की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगी। सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर पाने वाली सहकारी समितियों को भी तैयार करने का लक्ष्य है। हमने दो लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में पांच साल में एक अर्बन सहकारी बैंक बनाने का लक्ष्य भी रखा है। श्री शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को 'मल्टी-सेक्टर अप्रोच' के साथ देश के युवा उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर तबके के लोगों के सशक्तीकरण के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ-साथ कमजोर तबके के लोगों को भी मज़बूत करना है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के सिवा यह काम कोई और नहीं कर सकता। श्री शाह ने अपील की, 'अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कमजोर व्यक्तियों का सशक्तीकरण करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि यहां लांच हुए 'सहकार डिजी-पे' और 'सहकार डिजी-लोन' ऐप के माध्यम से छोटे से छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

देश में कोऑपरेटिव के लिए अपार सभावनाएं

श्री शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) ने अमूल को विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान और इफको को दूसरा स्थान प्रदान किया है, जो यह दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का विचार और संस्कृति अप्रासंगिक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अमूल आज देश में श्वेत क्रांति की वाहक बनी है। अमूल देश के 36 लाख किसान सदस्यों, जिनमें 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, को साथ जोड़कर 18 हजार ग्रामीण समितियों और 18 जिला संघों के माध्यम से देशभर में तीन करोड़ लाख लीटर दूध रोजाना इकट्ठा कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2024-25 में अमूल का टर्नओवर 90 हजार करोड़ रुपए को पार कर गया, जो यह बताता है कि ये लाखों किसान एकसाथ छोटी पूंजी से शुरू कर इतना बड़ा कोऑपरेटिव वर्षों से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। यह हमारे देश में कोऑपरेटिव के लिए उपलब्ध अपार सभावनाओं को बताता है।

इफको को मिला विश्व की दूसरी शीर्ष संस्था होने का गौरव

श्री शाह ने कहा कि इफको को विश्व की दूसरे नंबर की सहकारी संस्था का स्थान मिला है। इफको ने 41 हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर और तीन हजार करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि इफको कोऑपरेटिव सोसायटीज की सोसायटी है और देशभर में 35 हजार कोऑपरेटिव समितियों, जिनमे अधिकतर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) और मार्केटिंग से जुड़ी हुई समितियां हैं, इसके सदस्य हैं। लगभग पांच करोड़ से अधिक किसान इन समितियों के माध्यम से इफको के सदस्य बने हैं और आज इफको 93 लाख मीट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर हमारे देश की हरित क्रांति का स्तंभ बन गया है। उन्होंने कहा कि आज इफको की नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ब्राजील, ओमान, अमेरिका, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में निर्यात हो रहे हैं। ■

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर बोले पीएम श्री नरेन्द्र मोदी

स्वाधीनता सेनानियों का गीत होने के साथ ही शाश्वत प्रेरणा भी है

सहकार जागरण टीम

वंदे मातरम् केवल एक शब्द नहीं है - यह एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है और एक पवित्र संकल्प है। यह मां भारती के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। यह शब्द हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है, वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और भविष्य को यह विश्वास दिलाने का साहस देता है कि कोई भी संकल्प पहुंच से दूर नहीं है। वंदे मातरम् देश के स्वतंत्रता संग्राम और हर भारतीय की भावनाओं की आवाज बना। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह विचार व्यक्त किया।

वंदे मातरम् का सार है भारत, मां भारती जो देश का शाश्वत विचार है

भारत की अवधारणा और उसके पीछे की दार्शनिक शक्ति वैश्विक शक्तियों के उत्थान और पतन से अलग होने और स्वतंत्र अस्तित्व की एक विशिष्ट भावना में निहित होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब इस चेतना को लिखित और लयबद्ध रूप में अभिव्यक्त किया गया तो वंदे मातरम् जैसी रचना का जन्म हुआ। यही कारण है कि औपनिवेशिक काल में वंदे मातरम् इस संकल्प का उद्घोष बन गया कि देश स्वतंत्र होगा, मां-भारती की दासता की बेड़ियां टूट जाएंगी और उसकी संतानें अपने भाग्य की निमार्ता स्वयं बनेंगी।

वंदे मातरम् हर परिस्थिति काल में प्रासंगिक

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के इन शब्दों को याद करते हुए कि बंकिमचंद्र का आनंदमठ केवल एक उपन्यास नहीं है–यह एक स्वतंत्र भारत का स्वप्न है, प्रधानमंत्री ने आनंदमठ में वंदे मातरम् के गहन महत्व पर बल दिया और कहा कि बंकिम बाबू की रचना की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक भावना गहरे अर्थ रखती है। यंपि यह गीत औपनिवेशिक काल में रचा गया था, फिर भी इसके शब्द

सदियों की गुलामी की छाया में कभी सीमित नहीं रहे। यह पराधीनता की स्मृतियों से मुक्त रहा, और इसीलिए वंदे मातरम् हर युग और हर काल में प्रासंगिक बना हुआ है।

श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेज भारत को हीन और पिछड़ा बताकर अपने शासन को उचित ठहराने की कोशिश करते थे। लेकिन वंदे मातरम् की पहली पंक्ति ही इस झूठे प्रचार को पूरी ताकत से ध्वस्त कर देती है। इसलिए, वंदे मातरम् सिर्फ. आजादी का गीत नहीं था, इसने करोड़ों भारतीयों के सामने एक स्वतंत्र भारत की एक तस्वीर भी पेश की, यानी सुजलाम सुफलाम भारत का सपना। स्वतंत्रता आंदोलन का शायद ही कोई अध्याय हो जहां वंदे मातरम् किसी न किसी रूप में मौजूद न हो। वर्ष 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम् गाया था। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर अंग्रेजों ने राष्ट्र को बांटने का खतरनाक प्रयोग किया, तो उस समय वंदे मातरम् इस तरह की साजिशों के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा था। बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान सड़कें वंदे मातरम् की आवाज से गूंज उठी थीं।

यह याद करते हुए कि जब बारीसाल अधिवेशन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, तब भी उनके होठों पर शब्द थे - वंदे मातरम्, श्री मोदी ने कहा कि उस समय विदेश से देश की आजादी के लिए लड़ रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी एक-दूसरे को वंदे मातरम् कहकर अभिवादन करते थे। कई क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भी वंदे मातरम् गाया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी अनगिनत घटनाएं, इतिहास की अनगिनत तारीखें, विविध क्षेत्रों और भाषाओं वाले एक विशाल राष्ट्र में, ऐसे आंदोलन हुए जहां एक नारा, एक संकल्प, एक गीत हर आवाज में गूंजता था - वंदे मातरम् ।

वैदिक श्लोक का हवाला देते हुए, 'यह देश की भूमि हमारी माता है, हमारी जननी है, और हम इसकी संतान हैं,' श्री मोदी ने कहा कि वैदिक काल से ही भारत के लोग राष्ट्र की मातृरूप में पूजा करते आए हैं। इसी वैदिक विचार ने वंदे मातरम् के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में नई चेतना का संचार किया। भारत में मां जन्म देने वाली, पालन-पोषण करने वाली और जब उसकी संतान संकट में होती है, तो वह संकटों को हरने वाली भी होती है। मां भारती अपार शक्ति रखती है, विपत्ति में हमारा मार्गदर्शन करती है और शत्रुओं का नाश करती है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति के दिव्य अवतार के रूप में देखने की धारणा ने एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से शामिल करने का संकल्प लिया गया था। इस दृष्टिकोण ने भारत को एक बार फिर एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखने में सक्षम बनाया, जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे हो।

वंदे मातरम् की भावना ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को किया आलोकित

वंदे मातरम् को स्वतंत्रता के शहीदों का गीत होने के साथ-साथ इसे स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाला गीत भी करार देते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का है जो ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी हो; एक ऐसा राष्ट्र जो ज्ञान और नवाचार की शक्ति से समृद्ध हो, और एक ऐसा राष्ट्र जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर हो। हाल के वर्षों में दुनिया द्वारा भारत के वास्तविक स्वरूप के उदय को देखे जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व प्रगति और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसके उभरने के बारे में बताया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् की भावना ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को आलोकित किया था। इस सदी को भारत की सदी बनाने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से कहा कि इसे हासिल करने की ताकत भारत और उसके लोगों में निहित है। इस संकल्प को साकार करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है। ■

राष्ट्र जागरण का प्रथम मंत्र है 'वंदे मातरम्'

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया है। निश्चय ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की चेतना वंदे मातरम् गीत से ही मिली होगी, क्योंकि भारत की आजादी के दीवाने सपूतों ने 'वंदे मातरम्' बोलते हुए हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार की राजधानी पटना में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि यह उन सभी महान आत्माओं की इच्छा और कल्पना का भारत बनाने का और वंदे मातरम् गीत से प्रेरणा लेकर वर्ष 2047 तक महान भारत की रचना का समय है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महान भारत के लिए जो स्वप्न देखे थे, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में उन स्वप्नों को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों से कई काम हुए हैं। वंदे मातरम् के सामूहिक गान के साथ ही भारत की चेतना की पुनर्जागृति का चरणबद्ध प्रयास शुरू हुआ है। हमारा जीवन वंदे मातरम् के मंत्र और उसमें निहित भाव के अनुरूप हो, इसके लिए देश भर में एक साथ अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान फिजिकल के साथ-साथ डिजिटल स्वरूप में सोशल मीडिया पर भी हर भाषा में चलेगा और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में 'वंदे मातरम्' लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह तय किया है कि 'वंदे मातरम्' की 150वीं जयंती को हम स्वदेशी के लिए भी समर्पित करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की रचना स्वदेशी के बिना संभव ही नहीं है। स्वदेशी संकल्प पत्र का सामूहिक पाठ करके श्री शाह ने कहा कि 'वंदे मातरम्' की 150वीं जयंती पर देशवासी स्वदेशी को अपनाने का संकल्प लें और 2047 तक भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल हों और एक बार फिर भारत माता को अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लें। यह भारतीय चेतना की जागृति का दिन है, क्योंकि महान स्वतंत्रता सेनानी बंकिमचंद्र जी ने इसी दिन 'वंदे मातरम्' गीत लिखा था। इस गीत की रचना कर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का एक ऐसा महामंत्र दिया, जो भारत की आजादी का उद्घोष बना।

'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर श्री शाह ने सोशल मीडिया पर भी अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई अहम पड़ाव आए, जब गीतों, कलाओं ने लोकभावनाओं को सहेजकर आंदोलन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना के युद्धगीत हों, आजादी के आंदोलन में सेनानियों के गान या आपातकाल के विरुद्ध युवाओं के सामूहिक गीत हों, इन गीतों ने भारतीय समाज को स्वाभिमान की प्रेरणा दी और एकजुट भी बनाया। इसने हमें याद दिलाया कि भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक भू-सांस्कृतिक राष्ट्र है और इसकी एकता हमारी संस्कृति और सभ्यता से आती है। जैसा कि महर्षि अरबिंद ने कहा है कि बंकिम आधुनिक भारत के एक ऋषि थे, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से राष्ट्र की आत्मा को पुनर्जीवित किया। औपनिवेशिक भारत के सबसे अंधकारमय काल में लिखा गया 'वंदे मातरम्' राष्ट्र के जागृति का प्रभात-गीत बना। ■

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर पटना में आयोजित समारोह को श्री अमित शाह ने किया संबोधित

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उद्घोषणा है 'वंदे मातरम्'

यह केवल राष्ट्रीय गीत ही नहीं, बल्कि बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय द्वारा 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की प्रथम उद्घोषणा है

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने ब्लॉग में लिखा कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई अहम पड़ाव आए, जब गीतों, कलाओं ने अलग-अलग रूपों में लोकभावनाओं को सहेज कर आंदोलन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। ऐसा ही है भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' है, जिसका इतिहास किसी युद्ध भूमि से नहीं, बल्कि एक विद्वान बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के शांत लेकिन अडिग संकल्प से शुरू होता है। सन्1875 में जगद्धात्री पूजा (कार्तिक शुक्ल नवमी या अक्षय नवमी) के दिन उन्होंने उस स्तोत्र की रचना की जो भारत की स्वतंत्रता का शाश्वत गीत बन गया। 'वंदे मातरम्' केवल भारत का राष्ट्रीय गीत ही नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता आन्दोलन का प्राण ही नहीं, बल्कि यह बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय द्वारा 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की प्रथम उद्घोषणा है। इसने हमें याद दिलाया कि भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक भू-सांस्कृतिक राष्ट्र है - जिसकी एकता उसकी संस्कृति और सभ्यता से आती है।

अपने एक पत्र में बंकिम बाबू ने लिखा- 'मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि मेरे सभी कार्य गंगा में बहा दिए जाएं। यह श्लोक ही अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा।' औपनिवेशिक भारत के सबसे अंधकारमय काल में लिखा गया 'वंदे मातरम्' जागृति का प्रभात गीत बन गया। रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1896 में 'वंदे मातरम्' को धुन में पिरोया, जिससे इसे वाणी और अमरता प्राप्त हुई और यह गीत भाषा व क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में गूंज उठा। सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल अनुवाद किया और पंजाब में क्रांतिकारियों ने इसे गाते हुए ब्रिटिश राज को खुली चुनौती दी। 1905 में बंग-भंग आंदोलन के दौरान 'वंदे मातरम्' के सार्वजनिक पाठ पर प्रतिबंध लगा था, फिर भी 14 अप्रैल, 1906 को बारीसाल में हजारों लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की, जहां पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर लाठीचार्ज करके 'वंदे मातरम्'का नारा लगाते हुए पुरुषों व महिलाओं को लहूलुहान कर दिया।

वहां से 'वंदे मातरम्' का मंत्र गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ कैलिफोर्निया पहुंच गया। यह आजाद हिंद फौज में उस समय गूंजा, जब नेताजी के सैनिक सिंगापुर से मार्च कर रहे थे। वर्ष 1946 के 'रॉयल इंडियन नेवी' की क्रांति में भी 'वंदे मातरम्' की गूंज हुई, जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया। खुदीराम बोस, अशफाकउल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद से लेकर तिरुपुर कुमारन तक सबका नारा एक ही था। यह अब सिर्फ.एक गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की सामूहिक आत्मा की आवाज बन गया।

महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था, 'वंदे मातरम्' में 'सबसे सुस्त रक्त को भी जगाने की जादुई शक्ति' थी। महर्षि अरबिंद ने इसीलिए कहा था कि यह 'भारत के पुनर्जन्म का मंत्र' है। 15 अगस्त, 1947 को सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने पूरा 'वंदे मातरम्' गाकर आजाद भारत के हृदय के पहले स्पंदन को झंकृत किया। वहीं, 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर इसको सम्मान दिया और वहीं से यह हम सबके लिए एक राष्ट्र चेतना का गान बना।

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से भारत सरकार की ओर से अगले एक वर्ष तक अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्णय से देश की युवा पीढ़ी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के विचार को आत्मसात कर पाएगी। 'वंदे मातरम्' स्वतंत्रता का गीत है, अटूट संकल्प की भावना है और भारत के जागरण का प्रथम मंत्र है। राष्ट्र की आत्मा से जन्मे शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वे सदैव जीवित रहते हैं, पीढ़ियों तक गूंजते रहते हैं। ■

रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें

सहकार जागरण टीम

- एक विकसित भारत की यात्रा में ये ट्रेनें साबित होंगी मील का पत्थर
- वंदे भारत से जोड़े जा रहे पवित्र तीर्थस्थल भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा का संगम हैं

यह भारतीय रेलवे को बदलने का एक व्यापक अभियान है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। वंदे भारत भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीयों की बनाई गई ट्रेन है। यह हर भारतीय को गर्व से भर देती है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत करते हुए कही।

भारत में सदियों से तीर्थयात्रा को राष्ट्रीय चेतना का माध्यम माने जाने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट और कुरुक्षेत्र को राष्ट्र की विरासत का आध्यात्मिक केंद्र बताया। ये पवित्र स्थल अब वंदे भारत नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं। यह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा के संगम का प्रतीक है। यह विरासत शहरों को राष्ट्रीय प्रगति के प्रतीक के रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में तीर्थयात्रा के आर्थिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकासात्मक पहलों ने तीर्थयात्रा को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। तीर्थयात्रियों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस आमद ने राज्य भर के होटलों, व्यापारियों, परिवहन कंपनियों, स्थानीय कलाकारों और नाव संचालकों को निरंतर आय के अवसर प्रदान किए हैं। वाराणसी में सैकड़ों युवा अब परिवहन सेवाओं से लेकर बनारसी साड़ी के व्यवसाय तक, नए उद्यम शुरू कर रहे हैं। इस विकास ने उत्तर प्रदेश और वाराणसी में समृद्धि के द्वार खोले हैं।

विकसित वाराणसी के माध्यम से विकसित भारत के मंत्र को साकार करने के लिए शहर में निरंतर बुनियादी ढांचे के विकास होने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों, बेहतर सड़कों, गैस पाइपलाइन नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थापना, विस्तार और गुणात्मक सुधार हो रहा है। रोपवे परियोजना पर तेजी से प्रगति हो रही है और गंजारी व सिगरा स्टेडियम जैसे खेल बुनियादी ढांचे भी स्थापित हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य बनारस की यात्रा, वहां रहना और उसे अनुभव करना सभी के लिए एक विशेष अनुभव बनाना है।

वाराणसी के विकास की गति और ऊर्जा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने इस कल्पना के साथ समापन किया कि दुनिया भर से आने वाले प्रत्येक आगंतुक को बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी में एक अनोखी ऊर्जा, उत्साह और आनंद का अनुभव होना चाहिए। ■

भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है उत्तराखंड: प्रधानमंत्री

सहकार जागरण टीम

देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर और आदि कैलाश हमारी आस्था के प्रतीक पवित्र तीर्थस्थल हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। ये न केवल भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार करते हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह में कही। इस अवसर पर उन्होंने 8141 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया।

उत्तराखंड के विकास में बेहतर कनेक्टिविटी के अभूतपूर्व योगदान पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य में वर्तमान में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं जारी हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है। गौरीकुंड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को गति दे रही हैं।

पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड के प्रगति पर प्रधानमंत्री ने 'जहां चाह, वहां राह' कहावत का उल्लेख करते हुए कहा कि एक बार जब हम अपना लक्ष्य जान लेते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने का रोडमैप तेजी से सामने आ जाता है। उत्तराखंड की वास्तविक पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति में निहित होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर उत्तराखंड ऐसा करने का संकल्प ले, तो आने वाले वर्षों में वह स्वयं को 'विश्व की आध्यात्मिक राजधानी' के रूप में स्थापित कर सकता है। राज्य के मंदिरों, आश्रमों और ध्यान एवं योग केंद्रों को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है।

पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने सुगंधित पौधों, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों, योग और स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में की उल्लेखनीय प्रगति

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश-विदेश से लोग स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड आते हैं और यहां की जड़ी-बूटियों और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने सुगंधित पौधों, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों, योग और स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों का एक संपूर्ण पैकेज होना चाहिए। यह विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

उत्तराखंड के हर जीवंत गांव को एक छोटा पर्यटन केंद्र बनाने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य में होमस्टे, स्थानीय व्यंजनों और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही। उत्तराखंड की छिपी हुई संभावनाओं को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेला, फूलदेई और भिटौली जैसे त्यौहार पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। नंदा देवी मेला, जौलजीवी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवीधुरा मेला, श्रावणी मेला और मक्खन महोत्सव जैसे स्थानीय मेलों की जीवंतता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आत्मा इन उत्सवों में बसती है। इन स्थानीय त्यौहारों और परंपराओं को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए उन्होंने 'एक ज़िला, एक महोत्सव' जैसे अभियान का प्रस्ताव रखा। उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में फलों की खेती की अपार संभावनाओं और इन्हें बागवानी केंद्रों के रूप में विकसित करने की बात कहते हुए श्री मोदी ने ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और औषधीय पौधों को खेती का भविष्य बताया। ■

गुजरात में श्री अमित शाह ने किया सागर ऑर्गेनिक प्लांट का किया उद्घाटन

दुग्ध उत्पादों के निर्यात से देश की सहकारी समितियां हो रहीं समृद्ध

सहकार जागरण टीम

- बनासकांठा और दूधसागर डेयरी की अहम भूमिका
- घरेलू दुग्ध उत्पादन में कोऑपरेटिव डेयरी की हिस्सेदारी को बढ़ाने और निर्यात पर जोर
- भारतीय सेनाओं में सेवा का मार्ग प्रशस्त कर मेहसाणा का गौरव बनेगा मोतीभाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल

अमूल पूरे विश्व में सहकारिता का एक नंबर का ब्रान्ड बना है। इसकी नींव उस समय के कई महानुभावों ने मिलकर रखी और गुजरात के किसानों, पशुपालकों और राज्य के गांवो के लिए समृद्धि के द्वार खोलने का कार्य किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को राज्य में श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के मौके पर व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि मोतीभाई चौधरी के नाम से शुरू हुआ सागर सैनिक स्कूल आने वाले दिनों में गुजरात के कई ज़िलों के बच्चों के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सेवा का मार्ग प्रशस्त करेगा। 11 एकड़ भूमि पर फैला यह स्कूल 50 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें स्मार्ट क्लास रुम, हॉस्टल, लायब्रेरी, कैन्टीन आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने पीपीपी मॉडल के तहत देशभर में 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से मोतीभाई चौधरी सैनिक स्कूल निश्चित रूप से मेहसाणा के लिए गौरव का प्रतीक बनेगा।'' श्री शाह ने कहा कि माणसा के सभी नागरिको के लिए मोतीभाई एक आदर्श हैं। उन्होंने एक ऐसा आदर्श जीवन जिया, जो पूरी तरह महात्मा गांधीजी के सिद्धांतो पर आधारित, प्रामाणिक और पारदर्शी रहा। इससे बहुत से लोगों के जीवन में इन सभी गुणों का प्रसार हुआ।

सागर ऑर्गेनिक प्लांट की सार्थकता पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि अमूल ब्रान्ड के तहत विश्वसनीय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देश और दुनिया में पहुंचे और ऑर्गेनिक खेती

75 हजार नई प्राथमिक डेयरी ग्रामीण समितियों का गठन

श्री शाह ने कहा कि बनासकांठा और दूधसागर डेयरी ने मिलकर डेयरी के अर्थतंत्र को बदलने के लिए एक मॉडल दिया है। इस डेयरी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी हमने कई पहल की हैं जिनमें देशभर में 75 हजार नई प्राथमिक डेयरी ग्रामीण समितियों का गठन शामिल है। अमूल का 70 प्रतिशत कारोबार महिलाओं के योगदान से आता है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारी समितियों के दूध उत्पादन का 50 प्रतिशत देश और दुनिया तक पहुंचाकर पशुपालकों को फायदा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1960 में दूधसागर डेयरी में प्रतिदिन 3300 लीटर दूध एकत्रित होता था जो बढ़कर अब 35 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। यह डेयरी गुजरात के 1250 गांवों के पशुपालकों और राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 10 लाख से अधिक दूध उत्पादन समूहों के साथ जुड़ी हुई है। इसका टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए हो गया है। आठ आधुनिक डेयरी, दो मिल्क चिलिंग सेंटर, दो कैटल फीड प्लांट और एक सीमेंट उत्पादन केंद्र के साथ दूधसागर डेयरी अब गुजरात की श्वेत क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमूल के कुल टर्नओवर में 70 प्रतिशत योगदान हमारी माताओं-बहनों का है जो इससे आत्मनिर्भर बनती हैं।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात और देश के सभी पशुपालकों तक चक्रीय अर्थव्यवस्था का फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाई हैं, जो सहकारिता से जुड़े लाखों देशवासियों की समृद्धि का माध्यम बनेंगी। इनमें से पहली समिति पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान पर काम करेगी, दूसरी गोबर प्रबंधन के मॉडल विकसित करेगी, और तीसरी समति मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्क्युलर उपयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए हमें ऐसे एकीकृत सहकारिता का नेटवर्क सृजित करना होगा, जहां अधिकांश कार्य पारस्परिक सहयोग और सहकारिताओं के बीच में ही हो। सहकारिता मंत्रालय इस दिशा में अभिनव पहल करके डेयरी किसानों की सामर्थ्य बढ़ा रहा है।

करने वाले सभी किसानों को उनका मुनाफा मिले, इसके लिए यह प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऑर्गेनिक प्लांट के विस्तार से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानो की आय भी बढ़ेगी। श्री शाह ने कहा, ''लगभग 30,000 किलोग्राम की दैनिक क्षमता वाला यह संयंत्र राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तहत प्रमाणित है। एपीडा प्रमाणन के कारण उत्तरी गुजरात में प्राकृतिक खेती में लगे किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि उनकी उपज वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकेगी।'' इससे अन्नदाता किसानों की समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे और उनको बहुत फायदा होगा। श्री शाह ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों और उनके परिवारों से भी ऑर्गेनिक उत्पाद का उपयोग करने का आह्वान किया और कहा कि इससे उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। ■

भारत अब दुनिया के लिए विश्वसनीय एवं जिम्मेदार साझेदार : प्रधानमंत्री

सहकार जागरण टीम

- 140 करोड़ भारतीय पूरी गति के साथ बढ़ रहे आगे
- भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में हो गया है शामिल
- दुनिया की नजर में भारत एक विश्वसनीय और जिम्मेदार साझेदार

भारत 'कमजोर पांच' की श्रेणी से निकलकर दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। मुद्रास्फीति अब दो प्रतिशत से नीचे है, जबकि विकास दर सात प्रतिशत से अधिक है। चिप्स से लेकर जहाजों तक, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर व आत्मविश्वास से भरा है। भारत अब आतंकवादी हमलों के बाद चुप नहीं रहता, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से निर्णायक प्रतिक्रिया देता है व दुश्मन को धूल चटाता है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कही। कोविड-19 को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उस दौरान दुनिया भर में अटकलें लगाई जा रही थीं कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतने बड़े संकट से कैसे उबर पाएगा। लेकिन भारत ने हर अटकल को गलत साबित कर दिया। भारत ने इस संकट का डटकर सामना किया, तेजी से अपने टीके विकसित किए, रिकॉर्ड समय में टीकाकरण किया और इस संकट से उबरकर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा।

भारत का विकास वैश्विक अवसरों को दे रहा आकार

श्री मोदी ने ईएफटीए व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का विकास आज वैश्विक अवसरों को आकार दे रहा है। यूरोपीय देशों ने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। जी-7 देशों के साथ भारत के व्यापार में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। दुनिया अब भारत को एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और लचीले साझेदार के रूप में देखती है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक और ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल निर्माण तक, भारत में निवेश की लहर चल रही है। दुनिया भर के देश यहां पैसा लगाना चाहते हैं। ये निवेश भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने में मदद कर रहे हैं।

भारत की उपलब्धियों के पीछे असली ताकत यहां के नागरिकों को बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि नागरिक अपनी क्षमता का पूर्ण एहसास तभी कर सकते हैं जब सरकार उन पर दबाव न डाले या उनके जीवन में हस्तक्षेप न करे। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण एक ब्रेक का काम करता है, जबकि अधिक लोकतंत्रीकरण प्रगति को गति देता है। बैंकिंग क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण और सुधार पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मोड में 50 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए। आज, भारत के प्रत्येक गांव में कम से कम एक बैंकिंग टचपॉइंट है। महिला स्वयं सहायता समूहों, छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, रेहड़ी-पटरी वालों और विश्वकर्मा साथियों को बिना बैंक गारंटी के लाखों करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। इससे रोजगार सृजन में मदद मिली। लोगों को जीविका का साधन मिला।

दूर-दराज के क्षेत्रों को भी मिल रहीं उन्नत मेडिकल सुविधाएं

ई-संजीवनी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उन्नत सुविधाएं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचती हैं, तो वे जीवन बदल देती हैं। अब हाई-स्पीड कनेक्टिविटी आधारित ई-संजीवनी सेवा के माध्यम से दूर-दराज के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग भी चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मरीज अपने फोन से सीधे विशेषज्ञ डॉक्टरों से जुड़ सकते हैं। ई-संजीवनी के जरिए 42 करोड़ से ज्यादा ओपीडी परामर्श उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ■

आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाते हुए पीएम श्री नरेन्द्र मोदी बोले

आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही सेना

सहकार जागरण टीम

जब दुश्मन सामने हो और युद्ध आसन्न हो, तो जिस पक्ष के पास स्वतंत्र रूप से लड़ने की ताकत होती है, उसे हमेशा फायदा होता है। सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। पिछले एक दशक में भारत की सेनाएं आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ी हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौसैनिक पोत आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाते हुए कही। पिछले 11 वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर पिछले साल 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड ने नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां प्रदान की हैं। वर्तमान में औसतन हर 40 दिनों में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस और आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइलों ने अपनी क्षमता साबित की। दुनिया भर के कई देशों ने अब इन मिसाइलों को खरीदने की रुचि व्यक्त की है। भारत तीनों सेनाओं के लिए हथियारों और उपकरणों के निर्यात की क्षमता का निर्माण कर रहा है। भारत का लक्ष्य दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में शामिल होना है। पिछले एक दशक में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुने से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। इस सफलता का श्रेय रक्षा स्टार्टअप्स और स्वदेशी रक्षा इकाइयों को है।

आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में, जहां राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं और प्रगति समुद्री मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय नौसेना वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया की

- **पिछले 11 वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन तीन गुना से भी ज्यादा, डेढ़ लाख करोड़ के पार**
- **औसतन हर 40 दिनों में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में हो रहे शामिल**

66 प्रतिशत तेल आपूर्ति और 50 प्रतिशत कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। भारतीय नौसेना इन मार्गों की सुरक्षा के लिए हिंद महासागर के संरक्षक के रूप में तैनात है। इसके अतिरिक्त, मिशन-आधारित तैनाती, समुद्री डकैती-रोधी गश्त और मानवीय सहायता अभियानों के माध्यम से भारतीय नौसेना पूरे क्षेत्र में एक वैश्विक सुरक्षा भागीदार के रूप में कार्य करती है।

भारतीय नौसेना द्वारा भारत के द्वीपों की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वैश्विक दक्षिण के सभी देश साथ-साथ आगे बढ़ें। भारत 'महासागर समुद्री विजन' पर काम कर रहा है और कई देशों के लिए विकास भागीदार बन रहा है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत दुनिया में कहीं भी मानवीय सहायता देने के लिए तैयार रहा है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक, आपदा के समय दुनिया भारत को एक वैश्विक साथी के रूप में देखती है। भारत के सशस्त्र बलों ने समय-समय पर विदेशों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कई अभियान चलाए हैं। यमन से लेकर सूडान तक, जब भी और जहां भी आवश्यकता पड़ी, उनके पराक्रम और साहस ने दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के विश्वास को और मजबूत किया है। भारत ने इन अभियानों के माध्यम से हजारों विदेशी नागरिकों की जान भी बचाई है।

भारत के सशस्त्र बलों द्वारा भूमि, समुद्र, वायु और हर परिस्थिति में राष्ट्र की सेवा करने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नौसेना भारत की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए समुद्र में तैनात है, जबकि वायु सेना आसमान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जमीन पर तपते रेगिस्तान से लेकर बर्फीले ग्लेशियरों तक सेना बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ चट्टान की तरह अडिग खड़ी है। ■

फरीदाबाद के सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में बोले श्री अमित शाह

सहकारिता, कृषि और मछली पालन से दूर हो रही गरीबी, बढ़ रहा रोजगार

सहकार जागरण टीम

- **क्षेत्रीय ताकत के साथ राष्ट्रीय प्रगति और हर क्षेत्र में भारत का वैश्विक नेतृत्व हमारा लक्ष्य**
- **महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, इसके लिए बढ़ाई जाए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या**
- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन- 'सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का सृजन करते हैं', को जमीन पर उतारने में क्षेत्रीय परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को *'सहकार से समृद्धि'* का मंत्र दिया है। सहकारिता, कृषि और मछली पालन से गरीबी दूर हो रही है और रोजगार बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को हरियाणा के सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) देश की समृद्धि का परिचायक नहीं होता, बल्कि समृद्धि तभी मानी जाती है जब हर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है। जीडीपी के साथ रोजगार, खासकर स्वरोजगार में वृद्धि से ही हम एक विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में देश भर में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल किए हैं। इनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण, तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ ही डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने की पहल शामिल हैं।

मिलेट्स को बढ़ावा देने के अभियान में राजस्थान के योगदान की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि सभी राज्यों को मिलेट्स के उत्पादन और प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से मिलेट्स को गरीबों को हर महीने पांच किलो मुफ्त अनाज दिए जाने की योजना का हिस्सा बनाने की अपील की। इससे मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही नई पीढ़ी को मिलेट्स खाने की आदत पड़ेगी और लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

श्री शाह ने कहा कि अभी भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जल्द सजा दिलाने में विलंब, कुपोषण और बौनापन जैसी कई समस्याएं हैं जिनसे देश को मुक्त करने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच पर बल देते हुए श्री शाह ने कहा कि ऐसे घृणित अपराध को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन्हें त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

मोदी सरकार में क्षेत्रीय परिषदों की सक्रियता और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 की तुलना में पिछले 11 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में लगभग ढाई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है

और हमने इन बैठकों को सार्थक भी बनाया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान क्षेत्रीय परिषद और स्थायी समिति की केवल 25 बैठकें ही हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के दौरान अब तक 64 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'टीम भारत' के दृष्टिकोण को उद्घोषित करती हैं। इन बैठकों में 1600 मुद्दों पर चर्चा हुई और उनमें से 1303 मुद्दों (81.43 प्रतिशत) का समाधान हुआ। श्री शाह ने कहा कि यह सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से ही संभव हो रहा है और अंतर-राज्य परिषद सचिवालय इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ■

हर क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर जोर

प्रधानमंत्री श्री मोदी का दृष्टिकोण है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का सृजन करते हैं। इसे जमीन पर उतारने में क्षेत्रीय परिषदों का बहुत महत्व है। संवाद, सहयोग, समन्वय और 'पॉलिसी सिनर्जी' के लिए क्षेत्रीय परिषदें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन परिषदों के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं को हल किया गया है। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की मूल भावना और भूमिका सलाहकारी है, लेकिन मोदी सरकार में इसे 'एक्शन ओरियंटेड प्लेटफॉर्म' के रूप में स्वीकारा गया है और इसके परिणाम भी मिले हैं। राज्यों के बीच, क्षेत्र और राज्यों के बीच और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ फॉलोअप के साथ मुद्दों को हमने स्वीकार किया है और इनके समाधान प्राप्त करने के लिए ठोस रास्ता भी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है - क्षेत्रीय ताकत के साथ राष्ट्रीय प्रगति और हर क्षेत्र में भारत का वैश्विक नेतृत्व, जो हमें महान भारत की रचना की ओर ले जाती है। श्री शाह ने कहा कि सभी राज्य जल संसाधन प्रबंधन और पानी की समस्या दूर करने के लिए आपसी समन्वय से काम करें।

उत्तरी परिषद के सदस्य राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य व संघ राज्यक्षेत्र के साथ-साथ बैठक में देश के लिए कई अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में बैंकिंग की उपलब्धता, जल बंटवारे, पर्यावरण, उच्च शिक्षा आदि से जुड़े मुद्दे, आपातकालीन सहायता प्रणाली तथा क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के मुद्दों पर विशेष विमर्श हुआ।

हमारी न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि इन नए कानूनों को लागू करने से काफी सकारात्मक नतीजे मिले हैं। नए कानूनों के तहत दोष-सिद्धि की दर में लगभग 25 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और दोषियों को समय पर सजा भी मिली है। इन कानूनों के प्रभावी अमल के लिए राज्य सरकारों को और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से जांच और फॉरेंसिक जांच से लेकर न्यायालयों को ऑनलाइन लिंक करने के लिए तकनीक को अपग्रेड करने का आह्वान किया। वहीं, श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हम सबकी साझी प्रतिबद्धता है।

कृषि क्षेत्र की दो योजनाओं का शुभारंभ करते हुए बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

सरकार ने किसानों के हित में किए व्यापक सुधार

सहकार जागरण टीम

भारत की विकास यात्रा में खेती की केंद्रीय भूमिका है। तेजी से विकसित हो रहे 21वीं सदी के भारत को एक मजबूत और सुधरी हुई कृषि प्रणाली की आवश्यकता है। बीज से लेकर बाजार तक हमने किसानों के हित में व्यापक सुधार लागू किए। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और सुगम बनाना था। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में 35440 करोड़ रुपए की खर्च वाली दो प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कही।

पिछले 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना होने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खाद्यान उत्पादन में लगभग नौ करोड़ मीट्रिक टन और फल व सब्जियों के उत्पादन में 6.4 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। शहद व अंडा उत्पादन 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है।

इस दौरान देश में छह प्रमुख उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों को 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं 100 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तक पहुंच गई हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को दो लाख करोड़ रुपए के बीमा दावे वितरित किए गए हैं। पिछले 11 वर्षों में किसानों के सहयोग और बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए 10 हजार से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए गए हैं।

भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए हर क्षेत्र में निरंतर सुधार और प्रगति आवश्यक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसी दृष्टिकोण के साथ देश के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 36 सरकारी योजनाओं को एकीकृत और समन्वित तरीके से एक साथ ला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना न केवल किसानों पर, बल्कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी या कलेक्टर पर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालती है।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य दलहन उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही देश की भावी पीढ़ियों को मजबूत बनाने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के किसानों ने गेहूं और चावल जैसे खाद्यानों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। इससे भारत दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में शामिल हो गया है। लेकिन पोषण के लिए सिर्फ.आटे और चावल से आगे देखने की जरूरत है। दालें पादप-आधारित प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर इस चुनौती का समाधान करने का प्रयास करता है। इससे पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दलहन की खेती का रकबा 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि इस मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और दालों की खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इस अवधि के दौरान कृषि बजट में लगभग छह गुना वृद्धि में यह प्राथमिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

पारंपरिक कृषि से हटकर अवसरों का विस्तार करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ■

सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए सुदृढ़ संचार जरूरी

सहकार जागरण टीम

सहकारिता समतामूलक समाज के विकास का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इसे ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के मुख्य आधार के रूप में स्थापित कर रही है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार के सहयोग से सहकारिता का देश के सुदूर गांवों तक विकास एवं विस्तार हो रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने हाल ही में इन उपलब्धियों और सहकारिता के क्षेत्र में मीडिया की पहुंच एवं प्रचार बढ़ाने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सहकारी क्षेत्र में संचार को मजबूत करने, नवीन रणनीतियों को अपनाने और मंत्रालय के उद्देश्यों के अनुरूप जन भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री गुर्जर ने 'भारत ऑर्गेनिक्स' की क्षमता पर जोर दिया और स्वास्थ्य एवं कल्याण के दृष्टिकोण से इसके प्रचार को प्रोत्साहित किया। सहकारिता से जन-जन से जोड़ने और सभी देशवासियों तक सहकारी कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को सबसे प्रभावी मंच के रूप में उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने संचार प्रयासों को सुदृढ़ करने, सूचना एवं मीडिया कवरेज का दायरा विस्तारित करने से संबंधित रणनीतियों को अपनाने पर बल दिया, जिससे मंत्रालय के उद्देश्यों के अनुरूप जनता की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। श्री गुर्जर ने कहा कि देश के सभी गांवों एवं पंचायतों तक सहकारिता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय

सहकारी क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संचार प्रयासों को सुदृढ़ करने, सूचना एवं मीडिया कवरेज का दायरा विस्तारित करने पर जोर

दो लाख नए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), डेयरी कोऑपरेटिव और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का अभियान चला रहा है, जिसमें अब तक 29,200 से अधिक समितियों का गठन भी हो चुका है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि समाज और ग्रामीणों के जीवन पर सहकारी पहलों के सकारात्मक प्रभावों को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया रील और यूट्यूब वीडियो जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना अब समय की मांग है। सोशल मीडिया वर्तमान समय में संचार का एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जो जनता को सहभागिता का अवसर प्रदान करता है, हमारे सहकारी अभियानों को बढ़ावा देता है और नागरिकों को हमारी नीतियों के प्रति आकर्षित करता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और सभी हितधारकों को सहकारी समितियों और लाभार्थियों के बीच सोशल मीडिया पर अधिक उपस्थिति और समावेशी पहुंच के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया और कहा कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करें। यह आउटरीच सहकारी समितियों के सदस्यों, लाभार्थियों और अन्य संबंधित हितधारकों को प्रभावी रूप से लक्षित करे, जिससे सहकारी पहलों की प्रसार और सहभागिता को बढ़ावा मिल सके।

सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के *'सहकार से समृद्धि'* के विजन के अनुरूप ग्रामीण किसानों एवं आमलोगों का जीवन सहकारिता के माध्यम से उन्नत हो रहा है, इसका प्रसार भी मीडिया के माध्यम से होना चाहिए। इससे सहकारिता के प्रति युवाओं का रूझान बढ़ेगा और उन्हें रोजगार के विविध अवसर स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकेंगे। इस बैठक में संयुक्त सहकारिता सचिव श्री आनंद कुमार झा, निदेशक श्री कपिल मीणा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। ■

आलू के उन्नत बीज तैयार करने की उल्लेखनीय पहल

सहकार जागरण टीम

- **सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने में मिलेगी मदद**
- **बनास डेयरी और बीबीएसएसएल के बीच हुआ समझौता**

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने किसानों तक उन्नत बीज पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। समिति ने बनास डेयरी के साथ एक समझौता कर आलू के उन्नत बीजों के उत्पादन और वितरण का फैसला किया है। इस समझौते से आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सहकारिता में सहकार की पहल को इससे बल मिला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी संस्थाओं के बीच साझेदारी के कई प्रकल्पों को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की इस पहल से बीज से बाजार तक की श्रृंखला को विकसित करने में मदद मिलेगी।

सहकारिता मंत्रालय की इस पहल को आगे बढ़ाते हुए बनास डेयरी और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर आलू किसानों को उन्नत बीज प्राप्त हो सके। बनास डेयरी प्रख्यात अमूल का हिस्सा है जो एशिया की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी है।

सहकारिता की दोनों प्रमुख समितियों के बीच की इस साझेदारी ने आलू की उन्नत खेती हो सकेगी। यह साझेदारी 'बीज से बाजार तक' एक व्यापक मूल्य श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखती है। इसका मकसद है प्रमाणित और रोग-मुक्त बीज आलू का उत्पादन करना, साथ ही वैज्ञानिक खेती के तरीके, अनुबंध खेती और बेहतर बाजार जुड़ाव को बढ़ावा देना है।

तकनीकी सुधार और सहकारी प्रयासों को मिलाकर, यह पहल खेती की पैदावार बढ़ाने, लागत और नुकसान घटाने तथा आलू उगाने वाले किसानों की आमदनी और स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में सहायक होगी । यह समझौता 10 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें बनास डेयरी के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी और बीबीएसएसएल के प्रबंध निदेशक चेतन जोशी भी उपस्थित थे। संग्राम चौधरी ने बनास डेयरी के 'डेयरी से आगे' विषय पर विस्तार पर प्रकाश डाला, जबकि श्री जोशी ने बीज आलू में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर बल दिया। ■

बोरखेड़ा सहकारी समिति अब बैंकिंग सेक्टर में कर रही कमाल

सहकार जागरण टीम

समय की नब्ज को पहचान कर बदल डाली अपनी कार्य पद्धति

राजस्थान के कोटा जिले की बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लोगों के बीच सफलता की मिसाल बन गई है। समय के साथ उसकी रफ्तार पकड़कर चलने में उसका कोई सानी नहीं है। समय की नब्ज को पहचान कर इस सहकारी समिति ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लिया है। कभी ग्रामीण क्षेत्र की यह सहकारी समिति अब शहरी क्षेत्र में कार्यरत हो चुकी है। यह पूरा ग्रामीण क्षेत्र शहरी निकाय में शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 1954 में स्थापित यह समिति सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्रदान करती थी। पहले वहां के किसानों की खेती बाड़ी की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हुई। लेकिन 1990 में समिति का कार्यक्षेत्र कोटा नगर निगम के दायरे में आ गया। शहरीकरण हो जाने से पूरे इलाके में खेती-किसानी बंद हो गई। ऐसे में समिति की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन वहां की इस समिति ने हार नहीं मानी। बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अपने स्वभाव व गतिविधियों में परिवर्तन कर सेवा जारी रखने का संकल्प लिया। समिति ने शहर व वहां के निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तीन शाखाओं के साथ व्यावसायिक तरीके से मिनी बैंक के रूप में कार्य प्रारंभ किया।

अपने कार्यक्षेत्र के निवासियों में बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए समिति ने विभिन्न लघु मासिक, साप्ताहिक और दैनिक बचत योजनाएं शुरू कीं। समिति के कर्मचारी छोटे उद्यमियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी बचत राशि एकत्र करते थे। उन्हें छोटी-छोटी बचत करने के लिए प्रेरित करते थे। आज यह समिति 90 करोड़ रुपए के डिपॉजिट और 35 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर न केवल वित्तीय सशक्तीकरण का उदाहरण है, बल्कि अपने ग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में अभूतपूर्व भूमिका निभा रही है। इससे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन भी आ रहा है।

मिनी बैंक के रूप में समिति अपने ग्राहकों को सावधि जमा पर अन्य बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज प्रदान करती है। समिति किसान विकास पत्र (एनएससी) पर ऋण की सुविधा देती है। वेतनभोगी कर्मचारियों को ऋण देती है। इसके अलावा उपभोक्ता ऋण, व्यवसाय ऋण, क्रेडिट कार्ड, गृह ऋण और अन्य ऋण प्रदान करती है। वरिष्ठ नागरिकों के जमा पर विशेष ब्याज भी देती है और लॉकर व ई-मित्र सुविधा भी है।

समिति का ई-मित्र प्लस सेंटर बीमा और आधार-लिंक्ड सुविधाओं से लेकर जाति और आय प्रमाण पत्र व उपयोगिता बिल भुगतान तक की महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएं प्रदान करता है। अपनी इन सेवाओं के जरिए समिति प्रदेश में सफलता की नई कहानी लिख रही है। देश के सफल सहकारी समितियों में इसकी गणना होती है। इसके लिए समिति को एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार और एनसीडीसी क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। समिति की योजना आने वाले दिनों में मिनी सरकारी सुपरमार्केट की स्थापना करना है। समिति सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी काम करने की तैयारी कर रही है। ■

फर्श से अर्श पर पहुंचकर सहकारी समिति बनी प्रेरणा स्रोत

सहकार जागरण टीम

भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर एक नए युग की शुरुआत की है। यह प्रशासनिक बदलाव के साथ एक विचारधारा का पुनरुत्थान है। इसी दिशा में बढ़ते हुए 'छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भानसोज' फर्श से अर्श तक का सफर तय कर अन्य के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन गई है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आरंग तहसील में स्थित भानसोज प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की स्थापना 17 मार्च 1959 को की गई थी। 50 किसानों ने 500 रुपए की पूंजी के साथ इसे शुरू किया था। आज इसके सदस्यों की संख्या 2464 तक पहुंच गई है। समिति ने अपने सदस्यों को 449.15 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया है। नवाचार, समर्पण और समावेशिता के साथ काम करते हुए समिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसका लाभ उसके सदस्यों को मिल रहा है। समिति किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है और सुविधाएं प्रदान कर रही है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

समिति अपने सदस्यों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है और उन्हें स्वरोजगार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। इससे रोजगार का सृजन हो रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। नई-नई आर्थिक गतिविधियों को फलने-फूलने का अवसर मिल रहा है। खास बात यह है कि सदस्य समिति से जो ऋण लेते हैं, उसे तय समय पर वापस भी कर देते हैं। इसके कारण समिति को कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता और जरूरत पड़ने पर वह अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने को तत्पर रहती है। समिति गांव में माइक्रो एटीएम की सुविधा भी प्रदान करती है। इससे ग्रामीणों को नकदी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, उन्हें गांव में ही रुपए मिल जाते हैं और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। समिति के सहयोग से ग्रामीण खेती में भी विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। किसान खेती की आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं। उच्च गुणवत्तायुक्त खाद, बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फसलों का अधिक उत्पादन हो रहा है और उनको आर्थिक लाभ हो रहा है। खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए भी समिति अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती है। समिति की मदद से किसान इन उपकरणों को खरीद कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनके समय व धन दोनों की बचत हो रही है। वे अब जल्द व आसानी से अपना काम संपन्न कर पा रहे हैं और अधिक उत्पादन ले रहे हैं।

किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विकास के लिए सरकार सहकारी समितियों के विस्तार पर जोर दे रही है। सरकार का लक्ष्य हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति की स्थापना का है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि दो लाख प्राथमिक सहकारी समितियां रजिस्टर होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स, डेयरी या मत्स्य सहकारी समिति न हो। ऐसा होते ही पूरे देश में सहकारिता की पहुंच हो सकेगी, जिससे तहसील और जिले की संस्थाएं बनेंगी और राज्य की संस्थाओं को भी नई ताकत और गति मिलेगी। ■

सौर ऊर्जा का उत्पादन कर किसानों ने दिखाई नई राह

सहकार जागरण टीम

जहां चाह, वहां राह इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है गुजरात के खेड़ा जिले की ठसरा में स्थित ढुंडी गांव के किसानों ने। ये किसान सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी समिति गठित कर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्र को नई दिशा दिखा रहे हैं। सौर ऊर्जा की मदद से ये किसान जहां अपनी फसलों की सिचाई कर रहे हैं, वहीं अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री कर ये पैसा भी कमा रहे हैं।

भारत की पहली सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी समिति का गठन

सन 2016 में नौ किसानों ने मिलकर भारत की पहली सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इन किसानों ने गांव में 10.8 किलोवाट के तीन, आठ किलोवाट के तीन और पांच किलोवाट के तीन संयंत्रों की स्थापना की। गांव में वर्तमान में 79.4 किलोवाट के नौ संयंत्र कार्यरत हैं। इन संयंत्रों से रोज 350 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

सौर ऊर्जा की मदद से अब ये किसान पंप चलाकर फसलों की समय पर सिचाई कर रहे हैं। अब वे अपनी सुविधानुसार दिन में पंप का संचालन कर पा रहे हैं। इससे अब उन्हें रात में सिंचाई करने से छुटकारा मिल गया है। पहले ये किसान पंप चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए उन्हें रोज 500 से 700 रुपए खर्च करने पड़ते थे। डीजल लाने के लिए उन्हें गांव से बाहर जाना पड़ता था। डीजल से पंप चलाने पर प्रदूषण भी फैलता था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था। लेकिन सौर ऊर्जा का उत्पादन और उसका इस्तेमाल करने से किसानों को पैसे की भी बचत हो रही है। स्वच्छ व ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।

एमजीवीसीएल के साथ 25 वर्षों के लिए परचेज पावर एग्रीमेंट

किसान अतिरिक्त ऊर्जा को मध्य गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल) को 4.63 रुपए की दर से बेचकर आमदनी भी कर रहे हैं। इसके लिए किसानों ने कंपनी के साथ 25 वर्षों के लिए परचेज पावर एग्रीमेंट (पीपीए) किया है। ढुंडी गांव के किसानों से प्रेरित होकर दूसरे गांवों के किसानों ने भी सौर ऊर्जा का उत्पादन और इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वडोदरा के निकट मुजकुवा गांव के किसानों ने सौर ऊर्जा से पंप का संचालन शुरू कर दिया है। अब वे अपनी फसलों की सिंचाई समय पर पर्याप्त रूप से कर पा रहे हैं। इसके उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो रहा है।

ढुंडी गांव के किसानों के इस अभिनव प्रयोग ने देश के दूसरे किसानों को भी एक नया रास्ता दिखाया है। इससे प्रेरित होकर गुजरात व देश के दूसरे राज्यों के किसान भी सौर ऊर्जा का उत्पादन और उसके इस्तेमाल की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने ढुंडी गांव का दौरा कर किसानों के इस नए प्रयोग को देखा और उसकी सराहना की। सरकार भी किसानों को सौर ऊर्जा का उत्पादन और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ढुंडी गांव के किसानों ने दूसरे किसानों में उम्मीद की किरण जगाई है। ■

एस. महेंद्र देव

के. के. त्रिपाठी

विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की सामर्थ्य

देश में सहकारिता का रणनीतिक विकास और विस्तार हो रहा है। भारतीय कृषि को लाभकारी और एक आकर्षक व्यवसाय बनाने की दिशा में भारत सरकार और सहकारिता मंत्रालय सराहनीय पहल कर रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की सामूहिक शक्ति की अहम भूमिका होगी, क्योंकि ग्रामीण किसानों और अल्प साधन वाले समुदायों के आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन में 8.5 लाख सहकारी समितियों और उनसे जुड़े 29.2 करोड़ देशवासियों की सहभागिता प्रभावी सिद्ध हो रही है। लोकतांत्रिक स्वामित्व के माध्यम से ये सहकारी समितियां स्थानीय कौशल और सामूहिक इच्छाशक्ति के माध्यम से कृषि एवं अन्य उत्पादों को ग्रामीणों की समृद्धि में बदलने की अपार क्षमता रखती हैं। उत्पादकता को जन भागीदारी के साथ जोड़कर और डेयरी से लेकर उर्वरक तक 30 से अधिक कार्यक्षेत्रों में लाभ से पहले लोगों को प्राथमिकता देकर सहकारी समितियों ने सामाजिक समानता एवं समावेशी दक्षता के बीच एक व्यावहारिक संबंध स्थापित किया है। इससे एकजुटता और सह-अस्तित्व की भावना को भी बल मिला है।

सहकारी समितियां ऋण सेवाएं प्रदान करने के अलावा करीब 30 क्षेत्रों में विविध गैर-ऋण गतिविधियों का भी संचालन कर रही हैं। इनमें डेयरी, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, औद्योगिक, उपभोक्ता, श्रम, आवास, अस्पताल, सेवाएं, प्रसंस्करण, उत्पादक एवं विपणन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। भारत का कोऑपरेटिव मॉडल कृषि क्षेत्र के बिखरे हुए लघु उद्यमों को मजबूत सामुदायिक स्तर के कृषि-प्रसंस्करण एवं उत्पादन संकुलों में बदलने में सक्षम है, जहां जन भागीदारी के माध्यम से उत्पादकता बढ़ती है। 13 करोड़ से अधिक किसानों की भागीदारी के साथ 1.03 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) देश के 91 प्रतिशत गांवों में फैली हुई हैं और सहकारिता मंत्रालय दो लाख नई समितियों के गठन के द्वारा इसे शत-प्रतिशत गांवों तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। देश में कृषि-प्रसंस्करण एवं औद्योगिक सहकारी समितियों में 22 संघों और 22,735 समितियों के 25.31 लाख लोगों की भागीदारी है।

क्लस्टर-आधारित सहकारी निर्यात मॉडल पर जोर

क्लस्टर-आधारित सहकारी निर्यात मॉडल समय की मांग है। यह सहकारी मॉडल आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करता है, उत्पादकों को प्रसंस्करणकर्ताओं और वैश्विक बाजारों से जोड़ता है और उत्पाद दक्षता एवं लाभ को बढ़ाता है। देश की 19 राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी समितियों में से शुमार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) छोटे व सीमांत किसानों को निर्यात-उन्मुख समूहों में संगठित कर रही है। स्थानीय मूल्य संवर्धन, सामूहिक विपणन और वैश्विक बाजार एकीकरण को सक्षम बनाने के माध्यम से समावेशी आय वृद्धि को गति दी जा रही है। सहकारिता मंत्रालय एनसीईएल के रणनीतिक मार्गदर्शन में समितियों को विस्तार सेवाओं, ऋण तक पहुंच, आधुनिक तकनीक और निर्यात सुविधा प्रदान करने पर फोकस कर रही है। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता व मूल्य संवर्धन सुनिश्चित होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। क्लस्टर-आधारित निर्यात को एक स्थायी और समावेशी विकास मॉडल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

कृषि-निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना आवश्यक है। निर्यात परिणामों को अनुकूल बनाने के लिए जलवायु के अनुरूप कृषि, क्षेत्रीय फसल विशेषज्ञता और निर्यात क्षमता वाली बाजार मांग के आधार पर क्षेत्रों का मानचित्रण करके एक गतिविधि-क्लस्टर ढांचा विकसित करने से क्षेत्रवार सही फसलों को बढ़ावा मिलेगा और इससे खेती में प्राकृतिक लाभ भी मिलेंगे। उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट भौगोलिक दशाओं व पारंपरिक खेती पद्धतियों का लाभ उठाते हुए इसे केसर, सेब, अखरोट और फूलों की खेती के लिए एक उच्च-मूल्य वाले क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहीं, हल्दी, केला, चमेली, मसालों और समुद्री उत्पादों के लिए तमिलनाडु एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, जहां विविध कृषि और मजबूत बाजार संबंध पहले से ही उपलब्ध है।

क्लस्टर-आधारित सहकारी मॉडल में भारत के छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को उन्नत बनाने की क्षमता है। किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों पर केंद्रित निर्यात-उन्मुख गतिविधि समूहों में संगठित करने से उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और विश्वसनीय बाजार व्यवस्था बनेगी। किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करते हुए यह भारत को उच्च मूल्य वाली कृषि में एक वैश्विक नेता के रूप में पुनर्स्थापित करेगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ■

(प्रो. देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और डॉ. त्रिपाठी संयुक्त सचिव हैं)

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने अपने नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन (एनसीसीई) के जरिए 'कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट' के महत्वपूर्ण विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कृभको के हजीरा प्लांट के 38 अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

एनसीयूआई एवं इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी की अध्यक्षता में इफको के प्रबंध निदेशक श्री के जे पटेल व उप प्रबंध निदेशक श्री राकेश कपूर सहित सहकारी प्रतिनिधियों ने जॉर्डन कोऑपरेटिव कॉपोर्रेशन (जीसीसी) मुख्यालय का दौरा किया और जेसीसी के महानिदेशक श्री अब्देलफत्ताह एम.क्यू. अल-शलाबी के साथ सहकारी क्षेत्र में परस्पर सहयोग की नवीन संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। जिफको के एमडी एपी त्रिपाठी एवं सीवीओ दीपक यादव भी उपस्थित रहे।

एनसीयूआई ने नई दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आईआईटीएम) के स्टूडेंट्स के लिए 'सहकारिता' विषय पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन और उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने प्रतिभागियों का कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे मार्गदर्शन किया। कार्यकारी निदेशक श्री राजीव शर्मा व श्री रितेश दे और उप निदेशक श्री अनंत दुबे ने भी भागीदारी की।

एनसीयूआई के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने कोर्डेट कलोल द्वारा आयोजित सिलाई के छह माह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के आह्वान के अनुरूप सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी सहकारी समितियों के माध्यम से ही करें। सहकारी सदस्यों को इसका लाभांश मिलेगा और इससे आत्मनिर्भर भारत निर्माण संकल्प तेजी से साकार होगा।

एनसीयूआई और इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने नई दिल्ली में एनसीयूआई द्वारा आयोजित सहकार मेला का अवलोकन किया और मेले के सहभागी सहकारी बंधु भगिनियों के साथ संवाद किया। यहां देश के विभिन्न स्थानों की सहकारी समितियों के उत्पादों की बिक्री एक ही स्थान पर की गई। एनसीयूआई चार वर्षों से सहकार मेला आयोजित कर रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

एनसीयूआई के उपाध्यक्ष और दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. बिजेंदर सिंह ने नई दिल्ली में कोऑपरेटिव मेला-2025 का उद्घाटन किया। एनसीडीसी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य श्री धनंजय कुमार सिंह, कृभको की निदेशक श्रीमती शिल्पी अरोड़ा, एनसीयूआई की के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉ. सुधीर महाजन और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती सावित्री सिंह के साथ श्रीमती सोमा रॉय ने अपनी मौजूदगी से इस इवेंट की शोभा बढ़ाई।

बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। इन वर्षों में खेती का बजट करीब छह गुणा बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। हमारी सरकार ने खाद में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी दी है। अब तक तीन लाख 75 हजार करोड़ रुपए सीधे पीएम किसान सम्मान निधि के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन पर बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को ताकत मिलती है।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

NCUI हाट

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक : राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ